13 दिसंबर, 2021 करेंट अफेयर्स

1. मां उमिया धाम विकास परियोजना:

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के सोला में उमिया परिसर में इसके परिसर के साथ-साथ उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु:

अमित शाह ने रेलवे पुल सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

उमिया माता मंदिर मां उमिया को समर्पित है, जो कडवा पाटीदार संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं।

1,500 करोड़ रुपये की लागत से इस मंदिर और अन्य भवनों का विकास किया जाएगा।

यह 74,000 वर्ग गज जमीन में फैला होगा।

तीन दिवसीय समारोह:

मंदिर और अन्य भवन के शिलान्यास का 3 दिवसीय समारोह 11 दिसंबर, 2021 को शुरू किया गया था। इस समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 13 दिसंबर को वर्चुअल रूप से भाग लिया था।

यह एक 13 मंजिला परिसर है:

इस मंदिर के अलावा, उंझा में मुख्य मंदिर चलाने वाला एक ट्रस्ट, यूपीएससी और जीपीएससी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे पाटीदार युवाओं को प्रशिक्षण और छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए मंदिर से सटे एक 13 मंजिला परिसर का भी निर्माण करेगा।

उमिया माता मंदिर के बारे में:

उमिया माता मंदिर देवी उमिया का मंदिर है, जिन्हें कडवा पाटीदारों के कुल-देवी या कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में उंझा के केंद्र में स्थित है। इसने नवंबर 2009 में अपनी रजत जयंती मनाई।

उमिया धाम परिसर के बारे में:

अहमदाबाद, गुजरात में कडवा पाटीदार समुदाय द्वारा उमिया धाम परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस परिसर में एक मंदिर, चिकित्सा सुविधाएं, एक एनआरआई अतिथि गृह, सम्मेलन सभागार, वरिष्ठ नागरिक देखभाल सुविधाएं, लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, मनोरंजन और खेल सुविधाएं, और करियर और व्यवसाय विकास सुविधाएं शामिल होंगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में उमिया माता मंदिर:

2013 में, जॉर्जिया के मैकॉन में कडवा पाटीदार समाज द्वारा एक उमिया माता मंदिर भी बनाया गया था।

2. चेन्नई, नवीन जल प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है:

चेन्नई, नवीन जल प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए स्पंज सिटी में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्रमुख बिंदु:

- स्पंज सिटी की अवधारणा शहरी क्षेत्रों को अधिक पारगम्य बनाने, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अधिक खुले स्थान और इसे जलभृत में जाने की अनुमति देने का प्रयास करती है।
- चेन्नई का जल संसाधन विभाग पूरे शहर में छोटे जलाशयों में पुनर्भरण शाफ्ट खोदने की संभावना पर विचार कर रहा है।
- ये रिचार्ज शाफ्ट अक्सर 80-90 फीट तक खोदे जाते हैं। यह जल स्तर को फिर से भरने में सहायता करेगा।
- इस योजना के अनुसार, भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी के भंडारण के लिए छोटे जलाशयों और मंदिर के टैंकों का

उपयोग संरचनाओं के रूप में किया जा सकता है। पानी को अक्सर पीने योग्य बनाया जाता है, खींचा जाता है और शहर को आपूर्ति की जाती है।

स्पंज सिटी क्या है?

- स्पंज सिटी मूल रूप से बाढ़ प्रबंधन और पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे और जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक नया शहरी निर्माण मॉडल है।
- यह विचार 2000 में चीनी शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- 2014 में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) और राज्य परिषद ने इस विचार को "नगरवाद नीति" के रूप में स्वीकार किया था।
- यह तकनीक शहरी बाढ़, शहरी ताप द्वीप प्रभाव और जल संसाधनों की कमी को कम करने में सहायता कर रही है।
- यह बारिश के पानी को अवशोषित और रोककर और बाढ़ को कम करने के लिए इसका उपयोग करके पारिस्थितिक पर्यावरण और जैव विविधता में सुधार करता है।
- स्पंज सिटी नीतियां प्रकृति आधारित समाधान हैं, जो पानी को रोकने, भंडारण और सफाई के लिए प्राकृतिक परिदृश्य का उपयोग करती हैं।
- इस विचार को विशेष रूप से मानसून की दुनिया में जलवायु चुनौतियों के अनुकूलन के प्राचीन ज्ञान द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।

भारत में स्पंज सिटी मिशन:

- स्पंज सिटी का मूल विचार ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो शहर में गिरने वाले पानी को ले जाने और उपयोग करने के लिए अधिक पारगम्य हों।
- इन सभी को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन के आधार पर एक शहरी मिशन द्वारा प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सकता है।

भारत में स्पंज सिटी मिशन की आवश्यकता क्यों है?

- भारतीय महानगरों में शहरी बाढ़ एक साधारण घटना बन गई है।
- भारत की भूमि नीति ने शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाढ़ की पुनरावृत्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित या नियंत्रित नहीं किया है।
- शहरी शहरों में अभी भी उचित जल निकासी नेटवर्क का अभाव है।
- शहरों में कंक्रीट के ढाँचे से पानी की बर्बादी हो रही है।

Ole XPERT ONLINE LEARNING WITH EXPERTS

3. ख़बरों में 'सोलर हमाम':

सोलर हमाम एक स्थानीय रूप से डिज़ाइन किया गया और ब्रांडेड हीटिंग सिस्टम है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।

सोलर हमन का उद्देश्य क्या है?

सोलर हमाम का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के घरों में स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करना है। यह वनों को संरक्षित करने, महिलाओं को ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने से मुक्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है।

यह तकनीक कैसे महत्वपूर्ण है?

- इस तकनीक का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ों में परिवार ईंधन, चारा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आजीविका और रोजगार पाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 85% ग्रामीण परिवार पारंपरिक बायोमास ईंधन पर निर्भर हैं।
- हिमालयी क्षेत्र में 2000 मीटर की ऊंचाई पर, सर्दियां काफी कठोर होती हैं और पूरे साल ठंड रहती है। यह घरों को एक दिन में 16-17 घंटे तक ऊर्जा के स्रोत के रूप में लकड़ी की

आग पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है। इस क्षेत्र में, एकत्रित लकड़ी का लगभग 50% पानी गर्म करने और रहने की जगहों में उपयोग किया जाता है। इससे वनों का क्षरण होता है।

पिछली कहानी:

ग्रामीण घरों के लिए सरल और लागत प्रभावी सौर जल और तापन प्रणाली का विकास 2004 में शुरू किया गया था। 2008 में, एक कारीगर-निर्मित प्रोटोटाइप, सोलर हमाम, विकसित किया गया। ग्रामीण घरों में प्रदर्शन, सुरक्षा और रखरखाव के लिए सोलर हमाम का मूल्यांकन किया गया था। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में अब तक 1,200 से अधिक सोलर हमाम सिस्टम लगाए जा चुके हैं।

सौर हमाम के बारे में:

- सोलर हमाम एक एंटी-फ्रीजिंग आउटलेट प्रदान करता है। 30-35 मिनट की पहली सूरज रोशनी के भीतर यह सुबह 90 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान पर 15-18 लीटर गर्म पानी प्रदान करता है।
- गर्म पानी के लगातार बैच 15-20 मिनट अलग उपलब्ध होते हैं।
- सोलर हमाम के लिए स्थापना के बाद रखरखाव न्यूनतम है।

- यह ग्रामीण कारीगरों, मुख्य रूप से बढ़ई द्वारा निर्मित किया जाता है। इस प्रकार, इसने रोजगार पैदा करने में भी मदद की है।
- सोलर हमाम ने 2016-17 के लिए "हिमाचल प्रदेश स्टेट इनोवेशन अवार्ड" जीता था।

4. बैंक ऑफ बड़ौदा ने "बॉब वर्ल्ड वेव" लॉन्च किया:

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने हाल ही में "बॉब वर्ल्ड वेव" नामक एक पहनने योग्य भुगतान समाधान शुरू किया है।

ONLINE LEARNING WITH EXPERTS

मुख्य बिन्दु:

- बॉब वर्ल्ड वेव को डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए लॉन्च किया गया था।
- इस तकनीक में पूरे कार्य के दौरान बहुत अधिक दिलचस्पी देखी जा रही है और ऋणदाता इस अवसर का उपयोग अधिक सुविधाजनक और कैशलेस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए कर रहे हैं।

- यह अभिनव समाधान पूरी तरह से निवारक स्वास्थ्य कार्रवाइयां और आसान भुगतान लेनदेन प्रदान करने पर केन्द्रित है।

यह तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है?

"बॉब वर्ल्ड वेव" विकसित करने के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की थी। इसे वर्तमान एनएफसी आधारित तकनीक का लाभ उठाकर विकसित किया गया था।

इस समाधान की योग्यता:

- बॉब वर्ल्ड वेव एक "बैंक ऑन द गो" पहनने योग्य भुगतान समाधान है।
- इसे ग्राहकों के लिए निर्बाध और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह भुगतान का एक संपर्क रहित तरीका है जो सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करता है, खासकर COVID-19 के प्रकोप के बाद।
- यह उम्मीद की जा रही है कि छोटे टिकटों का 10% भुगतान अगले दो वर्षों में पहनने योग्य उपकरणों का उपयोग करके किया जाएगा।
- यह तकनीक ग्राहकों को अपने दिन-प्रतिदिन के लेनदेन को सुरक्षित और निर्बाध रूप से करने के लिए सशक्त बनाएगी।

इस तकनीक की क्या आवश्यकता है?

बढ़ती स्वीकृति के बुनियादी ढांचे के साथ, संपर्क रहित भुगतान तंत्र की मांग भी निरंतर बढ़ रही है। समग्र उपभोक्ता भावना भुगतान उद्योग में वियरेबल्स के स्थायित्व का समर्थन कर रही है।

बॉब वर्ल्ड वेव की मुख्य विशेषताएं:

- बॉब वर्ल्ड वेव पहनने योग्य समाधान ग्राहकों को अपने शरीर के तापमान, हृदय गति, Sp02 और रक्तचाप पर नजर रखे रहने की अनुमति देगा।
- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बॉब वर्ल्ड वेव सॉल्यूशन के साथ 3 महीने का एक विशेष मुफ्त वेलनेस पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य कोच, इंटरैक्टिव वीडियो कोचिंग और डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन के साथ वेलनेस पैकेज प्रदान किया जाएगा।
- यह सभी एनएफसी सक्षम पीओएस उपकरणों पर 5000 रुपये तक का संपर्क रहित भुगतान प्रदान करेगा। 5000 रुपये से अधिक का भुगतान पिन का उपयोग करके किया जा सकता है।
- बैंक ऑफ बड़ौदा एक डमी प्लास्टिक कार्ड भी प्रदान करेगा, जिसमें एक्सपायरी डेट और सीवीवी के साथ पहनने योग्य डिवाइस पर छपा कार्ड नंबर शामिल होगा। इस कार्ड से ग्राहक आसानी से ई-कॉमर्स लेनदेन कर सकेंगे।

Ole XPERT ONLINE LEARNING WITH EXPERTS

5. वैश्विक पेंशन रिपोर्ट:

हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि; एक वैश्विक पेंशन सूचकांक जिसने भारत की पेंशन प्रणाली को सूची में सबसे नीचे रखा, विश्वसनीय तुलनीय अंतरराष्ट्रीय डेटा के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

मुख्य बिन्दु:

- वैश्विक पेंशन सूचकांक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी और इसने भारत को अपनी पेंशन प्रणाली के लिए 43 देशों में से 40वें स्थान पर रखा है।
- यह रिपोर्ट एक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- यह सूचकांक स्थिरता, पर्याप्तता और अखंडता के कुछ मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया है।
- सूचकांक ने भारत को जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों की समान श्रेणी में रखा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के बारे में:

- एनपीएस ट्रस्ट, भारत में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का एक विशेष प्रभाग है। यह वित्त मंत्रालय के मूल प्रमुख के अधीन कार्य करता है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली है। यह एक ईईई (छूट-छूट-छूट) साधन है, जिसमें परिपक्वता पर पूरा कोष कर से बच जाता है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत, पूरी पेंशन निकासी राशि कर-मुक्त है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित भारत के सभी नागरिक स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी अनिवासी भारतीयों (NRI) को 29 अक्टूबर, 2015 को NPS की सदस्यता लेने की अनुमति दी। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बारे में:

पीएफआरडीए एक नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के मूल प्रमुख के अधीन कार्य कर रहा है। यह भारत में पेंशन का पर्यवेक्षण और विनियमन करता है। इसमें एक अध्यक्ष और छः से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। 6 सदस्यों में से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

6. यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अपनी अमूर्त विरासत सूची में जोड़ा:

हाल ही में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए इस अंतर सरकारी समिति ने अपने 16वें सत्र में, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को अंकित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिन्दु:

- यूनेस्को का 16वां सत्र 13 दिसंबर, 2021 से शुरू हो रहा है। इसका समापन 18 दिसंबर, 2021 को होगा।
- अब तक, दुनिया भर में कई हिस्सों में दुर्गा पूजा मनाई जाती थी। लेकिन एक आधिकारिक वैश्विक मान्यता लंबित थी।
- दुर्गा पूजा धर्म और संस्कृति का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। इसे बड़े ही शान से माना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बंगाली समुदाय द्वारा मनाया और मनाया जाता है।

दुर्गा पूजा के बारे में:

दुर्गा पूजा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। इसे दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार की

शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप से हुई है जो हिंदू देवी दुर्गा का सम्मान करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देता है। यह महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से लोकप्रिय है और पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और साथ ही बांग्लादेश जैसे देशों में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा दस दिनों का पर्व है। इनमें से अंतिम पांच दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

यह त्यौहार कब मनाया जाता है?

दुर्गा पूजा भारतीय कैलेंडर के अश्विन माह में मनाई जाती है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में सितंबर-अक्टूबर से मेल खाती है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है?

यूनेस्को के अनुसार, सांस्कृतिक विरासत वस्तुओं और स्मारकों के संग्रह पर समाप्त नहीं होती है। इसमें परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं जो पूर्वजों से विरासत में मिली हैं और वंशजों को हस्तांतरित की गई हैं। यह यूनेस्को द्वारा माना जाने वाला एक अभ्यास, अभिव्यक्ति, प्रतिनिधित्व, ज्ञान या कौशल है। अमूर्त विरासत में लोककथाओं, रीति-रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों, ज्ञान और भाषा जैसी गैर-भौतिक बौद्धिक संपदा सम्मिलित है। इसे यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा माना जाता है। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए

कन्वेंशन 2003 में इसकी रक्षा और बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था।

7. सुप्रीम कोर्ट ने यौनकर्मियों को जारी किए आधार, वोटर कार्ड:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वह किसी भी पेशे का हो।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेक्स वर्कर्स को वोटर आईडी, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिन्दु:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यौनकर्मियों को सूखा राशन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने आगे निर्देश दिया कि, समुदाय आधारित संगठनों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि के बाद यौनकर्मियों की सूची तैयार करते समय अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जारी करने से संबंधित स्थिति रिपोर्ट निर्देश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी यौनकर्मियों को उनके राशन कार्ड और अन्य पहचान प्रमाण मांगे बिना सूखा राशन वितरण जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

क्यों आया है ये फैसला?

एनजीओ 'दरबार महिला समन्वय समिति' की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश आया है। याचिका ने COVID-19 महामारी के बीच यौनकर्मियों के सामने आने वाली समस्याओं को उठाया। सुप्रीम कोर्ट यौनकर्मियों के कल्याण के लिए आदेश देता रहा है, 29 सितंबर, 2020 को अदालत ने केंद्र और अन्य से बिना पहचान प्रमाण मांगे उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराने को कहा था।